

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
96/2012 (रिफरेंस)	07.08.2012	07.06.2024
(GCMS 2012/00032)		

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

- 1-भैरा पिता नाराण गुर्जर निवासी दोतडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 2-रतन पिता नाराण गुर्जर निवासी दोतडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 3-उंकार पिता नाराण गुर्जर निवासी दोतडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 4-हेमराज पिता जीतू गुर्जर निवासी दोतडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 5-नाना पिता जीतू गुर्जर निवासी दोतडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 6-उदी बेवा जीतू गुर्जर मृतक के बजाए:-
6/1-रतनी बाई पुत्री जीतू गुर्जर निवासी दोतडी हाल ग्राम आलोड़ा बस्ती पटवार हल्का नाहरगढ़, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
- 7-सोहनलाल पिता सोला गुर्जर निवासी दोतडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 8-रंगलाल पिता सोला गुर्जर निवासी दोतडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 9-लछमण पिता सोला गुर्जर निवासी दोतडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 10-घीसीबाई पुत्री सोला गुर्जर निवासी दोतडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)



- 11-हगामी बेवा सोला गुर्जर निवासी दोतडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 12-उदयराम पिता हीरा गुर्जर निवासी दोतडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 13-धापू पुत्री हीरा गुर्जर निवासी दोतडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 14-रुकमणी बेवा हीरा गुर्जर निवासी दोतडी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मृतक नामतर्क)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :- श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक
श्री खुमराज कुमावत, अधिवक्ता विपक्षीगण

--:: निर्णय ::--

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम दोतडी, तहसील भदेसर की आराजी संख्या 264 मी रकबा 3.04 बीघा वक्त सेटलमेंट नाली दर्ज होकर राजकीय भूमि थी इसमें से विपक्षीगण को 1.05 बीघा का आवंटन किया गया। उक्त भूमि की किस्म नाली होने से इसे अन्य व्यक्तियों को आवंटन नहीं की जा सकती। उक्त नाले/नाली की भूमि को नामान्तरण संख्या 11 से विपक्षीगण नाराण, जीतू, हीरा व सोला पिता नोला गुर्जर के नाम दायर किया जो नियमों के विपरीत होने से पुनः बिलानाम सरकार दर्ज की जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी कर तलब किया गया विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री खुमराज कुमावत ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या संख्या का सूचना पत्र उसकी मृत्यु की सूचना के साथ प्राप्त होने पर उसके वारिसान को रेकार्ड पर लिया जिसमें से विपक्षी संख्या 4 व 5 प्रकरण में पहले ही पक्षकार संयोजित होने से शेष वारिस उदी की पुत्री रतनी बाई को पक्षकार संयोजित किया। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 14 के फोट होने तथा उसके वारिसान प्रकरण में पहले ही पक्षकार विपक्षी



संख्या 12 व 13 संयोजित होने से विपक्षी संख्या 14 का नामतर्क किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। अतः उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम दोतडी की आराजी संख्या 264 मी रकबा 3.04 बीघा वक्त सेटलमेंट नाला-नाली की दर्ज होकर राजकीय भूमि थी, जो कि अन्य निजी व्यक्तियों को आवंटन नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि यह नाला/नाली/तलाई/नाडी की आराजी है, तथा नाला/नाली/तलाई/नाडी के रूप में ही उपयोग हो सकती है। ऐसी आराजी पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है तथा ऐसा आवंटन राजस्व अधिकारी द्वारा किया गया है तो वो नल एण्ड वोर्ड होकर प्रभाव शून्य है व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण संख्या डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के आदेश दिनांक 02.08.2004 में अंकित बिन्दु संख्या 01 व 04 के विरुद्ध होने से नदी/नाला/कैचमेंट एरिया एवं पेटा के प्राकृतिक स्वरूप को नहीं बदल 15 अगस्त 1947 के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति रखने के आदेश पारित किये गये है। अतः रेफरेन्स आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि आराजी संख्या 264 मी रकबा 3.04 बीघा वक्त सेटलमेंट नाला-नाली दर्ज होने की बात गलत है तथा मौके पर कभी नाला या नाली नहीं रहा। राजकीय बिलानाम भूमि पर वर्षों के कब्जे के आधार पर विपक्षीगण को विधिवत् आवंटन हुआ वह करीब 40 वर्षों से काबिज होकर आदिनांक तक विपक्षीगण के कब्जे-काश्त में है। इस भूमि पर लाखों रुपये खर्च कर इस भूमि को उपजाऊ बनाया है जिसके चारों ओर बाउण्ड्री बनी हुई है और वर्तमान में काश्त हो रही है। अतः इस प्रकार रेफरेन्स के जरिये आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः भूमिधारी तहसीलदार, भदेसर के रेफरेन्स आवेदन को निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम दोतडी, तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 264 मी रकबा 3.04 बीघा किस्म नाला-नाली होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस भूमि में से नवीन आराजी नम्बर 264/2 रकबा 1.05 बीघा बने हैं जिसकी किस्म वर्तमान में रे.क. दर्ज है जो विपक्षीगण के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है जो कि नामान्तरण संख्या 99 के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है। आराजी नम्बर



264/2 रकबा 1.05 बीघा वर्तमान में अप्रार्थीगण के दर्ज रिकार्ड है, जिसकी किस्म वर्तमान में “रे.क.” है जो कि नियमों के विरुद्ध है, उक्त भूमि गत भू-प्रबंध में किस्म “नाला-नाली” दर्ज रेकार्ड रही है जिससे उक्त भूमि व्यक्ति विशेष के खातेदारी में रहने योग्य नहीं होने से बिलानाम किये जाने हेतु प्रार्थी तहसीलदार भदेसर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत जिला कलक्टर को अधीनस्थ किसी न्यायालय या राजकीय अधिकारी के द्वारा निर्णित प्रकरण या कार्यवाही के अभिलेख को मंगाने एवं परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा परीक्षण इस दृष्टि से किया जाता है कि प्रश्नगत निर्णय की विधिकता, औचित्य एवं कार्यवाहियों की नियमितता रही है या नहीं, इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत जिला कलक्टर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये राजस्व मामलों के अभिलेख को तलब कर परीक्षण कर सकता है और परीक्षण उपरान्त अपनी राय का उल्लेख करते हुए विवादित आदेश को निरस्त/संशोधित व बदलने के लिये माननीय राजस्व मण्डल को रेफर कर सकता है। उक्त दोनों प्रावधानों में समय सीमा विहित नहीं की गई है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से प्रार्थी तहसीलदार भदेसर द्वारा इस तथ्य को निर्विवाद रूप से प्रमाणित कराया गया है कि मौजा दोतडी, तहसील भदेसर की हाल आराजी नम्बर 264/2 रकबा 1.05 बीघा वर्तमान में विपक्षीगण के नाम पर दर्ज रिकार्ड है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2060-2063 के खाता संख्या 115 से होती है। इसके साथ ही इस नकल जमाबंदी से यह तथ्य भी प्रमाणित पाया जाता है कि आराजी संख्या 264/2 रकबा 1.05 बीघा, आराजी संख्या 264 मी रकबा 3.04 बीघा किस्म नाली से ही बने है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा नामान्तरण/नकल जमाबंदी/इत्यादि राजस्व रिकार्ड से सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म नाली की भूमि रही है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार किस्म तालाब पेटा की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 में निम्न प्रावधित किये गये है :-



16 Land on which Khatedari rights shall not accrue-

Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

- (iii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

88 All roads etc. and all land which are not the property of others belong to the State

- (1) All public roads, lanes, paths, bridges and ditches; all fences on or beside the all rivers, streams, lakes and tanks, all canals and watercourses, all standing and flowing water, and all lands wherever situated, which are not the property of individuals or of bodies of person legally capable of holding property are except in so far as any rights of such persons or bodies may be established in over the same and except, may be otherwise provided in any law for the time being in force, and are hereby declared to be, with all rihts in or over the same or appertaining thereto, the property of the State; and it shall be lawful for the Collector subject to the 64[order of the Commissioner] to dispose of them in such manner as may be prescribed subject always to the rights of way and all other rights of the public or of individuals legally aubsisting.
- (2) Where any property or any right in over any property is claimed by or on behalf of the State or by any person as against the State, it shall be lawful for the Collector, after formal inquiry of which due notice has been given to pass an order deciding the claim.
- (3) Any suit instituted in any civil court after the expiration of any year from the date of any order passed under sub-section (1) of sub-section 92) or, if one more appeals have been made against such orders within the period of limitation, then from the date of any order passed by the final appellate authority, shall be dismissed (although limitation has not been set up as a defence) if the suit is brought to set aside such order or if the relief claimed is inconsistent with such order; provided that in the case of an order under sub-section (2), the plaintiff has had due notice of such order.
- (4) Every person shall be deemed to have been due notice of an inquiry or order under this section, if notice there or has been given in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder.
- (5) Any order passed under sub-section (1) or sub-section (2) shall be enforceable by the Collector in the prescribed manner.

प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म नाला-नाली की भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित श्रेणी की आराजीयात है। धारा 88 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार इस प्रकार की भूमियां राजकीय भूमियों की श्रेणी में आती है, जिन पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है।



हस्तगत प्रकरण, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर द्वारा परित निर्णय रिट पीटीशन संख्या 1536/2004 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में दिये गये निर्देशों की पालना में क्रम में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1536/2004 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये हैं :-

"(3) Suggestions for restoring the catchment areas to their original shape and use:

Looking to the site visit by the State Level Expert Committee in September 2003 and General Survey Reports received from the District Collectors and Chairmen.

District Expert Committee, following suggestions are made:

1. All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.8.1947 should be declared as Govt. land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.
2. Demarcation of catchment areas should be done by construction pillars at suitable spacing depending upon size of the catchment area with the help of G.T. sheet of scale 1:25000 or 1:50000 and/or "Water Shed Atlas of Rajasthan" prepared by the State Remote Sensing Application Centre, Jodhpur.
3. Demarcation of drainage channels –
 - (i) In uninhabited areas this can be done by installing pillars at suitable spacing or by constructing side wall depending upon size of drainage channel and its importance.
 - (ii) In urban and rural areas, the demarcation of drainage channels must essentially be done by constructing side walls of appropriate height and thickness.
4. In the government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the government.
5. The drainage channels in the catchment areas should be got inspected by engineering professionals and Patwatis. Wherever there are obstructions in nalla, it should be suitably removed by constructing culverts, deepening and widening of nallas etc.
6. Wherever there are any construction activities, which may interfere with the flow of water in drainage channels, no objection certificate must be obtained from the irrigation department.
7. The Anicuts more than 2m height above deepest nalla bed should be identified. The height more than 2m should be dismantled.
8. Wherever residential colonies have been constructed obstructing flow in drainage channels, the obstruction must be removed and nallas may be deepened and constructed



9. On the periphery of lakes, ponds, water bodies in urban and rural areas, a pucca drain should be constructed on periphery of the water body to prevent entry of domestic, industrial and other waste in the water body.
10. For soil conservation work, suitable guidelines must be issued by the "Watershed & Soil Conservation Department" so that these works make minimum possible interference with the flow of water.
11. The district administration should specify places for dumping various types of waste material. If any body is found to dump the waste material in other places, particularly drainage channels, then suitable punishment should be provided in the law.
12. The government should use television, radio and newspapers to create awareness in this matter.
13. Possibility should be explored to use marble slurry as construction material, for filling depressions etc. as has been done for disposal of fly ash from thermal Power Houses.
14. The water quality of water bodies should regularly be monitored.
15. Wherever over-burden or waste materials generated from mines and processing units, have been dumped obstructing flow of water in drainage channels; diversion drains and check walls must be constructed. For that purpose, special condition should be incorporated in the lease/license agreement."
16. Having, given thoughtful consideration to the issue involved and the suggestions made, we direct the State Government to consider the recommendations of the Committee referred to above and chalk out a plan to take the effective steps. for restoring the catchment areas to their original shape. It is made clear that this order will not prevent the State Authorities from drawing up or taking further step more effectively to fulfill the object of the directions issued by this court. Three months' time is granted for giving positive shape to the suggestions. The interim order dated 9.4.2003 granted by this Court is made absolute.

माननीय न्यायालय द्वारा यहाँ स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये कि सरकार के स्वामित्व वाली झीलों और अन्य जल निकायों में, खातेदारी अधिकार। डूब क्षेत्र में निजी व्यक्तियों की भूमि को सरकार के स्वामित्व में लाया जाये। जहां भी आवासीय कॉलोनियों का निर्माण जल निकासी चैनलों में प्रवाह को बाधित कर रहा है, अवरोध को हटाया जाना चाहिए और नालों को गहरा और निर्माण किया जाना चाहिए। जलग्रहण क्षेत्रों को उनके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए। यह स्पष्ट गया है। माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में ही राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 6(16)राज-6/ 99/9 दिनांक 16.07.2003 से प्रचारित किया गया है कि जोहड गबाई तालाब नाडी आदि जल संग्रहण कार्यों हेतु उपयोग में आने वाले भूमि तथा जल



ग्रहण कार्यो के जो जल प्रवाह क्षेत्र में है आदि भूमियो का भविष्य में निर्माण कार्यो हेतु आवंटन नहीं किया जावेँ उन्हे फ्री रखा जावे।

इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर बैच द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 29.05.2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 10(03)राज-6/01/पार्ट/17 दिनांक 23.09.2011 से प्रचारित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियो, जिनमें खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते का आवंटन अवैध है। ऐसा देखने में आया है कि जिला कलेक्टरों द्वारा एवं उनसे नीचे के अधिकारियो द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियो का आवंटन किया जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमियो का आवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जावे। यदि पूर्व में कोई आवंटन कर दिये गये हो तो विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर निरस्त करावे तथा बेदखली की कार्यवाही करें। निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर बैच द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 29.05.2012 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये है :-

- 2 Instructions be issued restraining allotment of land falling in catchment areas of water reservoirs like Johar, Nala, Tank, river, pond etc. Infringement of instructions should be viewed seriously with follow-up action against the defaulting officers and the beneficiaries so that tendency of illegal allotment of land may be stopped at all levels.
3. Action may be taken for cancellation of allotments made in violation of section 16 of the Act of 1955 and other Rules and Regulations. Presently, details of the references sent to the Board of Revenue in regard to Ramgarh dam catchment area have been furnished to this court which are more than 400 by now. Similar drive for making reference to the Board of Revenue in regard to catchment areas of other water reservoirs in the State of Rajasthan should be taken up so that with the cancellation of illegal allotments followed by removal of encroachments, water may flow to reservoirs like river, dam, nala, pond, Johar etc without obstruction.

माननीय न्यायालय द्वारा यहाँ स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये कि जोहड़, नाला, टैंक, नदी, तालाब आदि जलाशयो के जलग्रहण क्षेत्रों में आने वाली भूमि के आवंटन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए जाएँ। निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियो और लाभार्थियो के खिलाफ अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अवैध की प्रवृत्ति को रोका जा सके। हर स्तर पर भूमि आवंटन रोका



जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं अन्य नियम एवं विनियम के उल्लंघन में किये गये आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में, रामगढ़ बांध जलग्रहण क्षेत्र के संबंध में राजस्व मंडल को भेजे गए संदर्भों का विवरण इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है, जो अब तक 400 से अधिक हैं। राजस्थान राज्य में अन्य जल जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों के संबंध में राजस्व बोर्ड को संदर्भित करने के लिए इसी तरह का अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि अवैध आवंटन को रद्द करने और अतिक्रमण हटाने के साथ नदी जैसे जलाशयों में पानी प्रवाहित हो सके। बांध, नाला, तालाब, जोहड़ आदि बिना रुकावट के।

2019 SSC Online SC 1510 जितेंद्र सिंह बनाम पर्यावरण मंत्रालय और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम समुदायों में निहित सामान्य भूमि से संबंधित मुद्दे में निर्देशित किया गया है :-

Protection of such village-commons is essential to safeguard the fundamental right guaranteed by Article 21 of our Constitution. These common areas are the lifeline of village communities, and often sustain various chores and provide resources necessary for life. Waterbodies, specifically, are an important source of fishery and much needed potable water. Many areas of this country perennially face a water crisis and access to drinking water is woefully inadequate for most Indians. Allowing such invaluable community resources to be taken over by a few is hence grossly illegal.”

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए ऐसे ग्राम-सामुदायों की सुरक्षा आवश्यक है। ये सामान्य क्षेत्र ग्राम समुदायों की जीवन रेखा हैं, और अक्सर विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। जल निकाय, विशेष रूप से, मत्स्य पालन और अत्यधिक आवश्यक पीने योग्य पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस देश के कई क्षेत्र हमेशा जल संकट का सामना करते हैं और अधिकांश भारतीयों के लिए पीने के पानी तक पहुंच बेहद अपर्याप्त है। इसलिए ऐसे अमूल्य सामुदायिक संसाधनों पर कुछ लोगों को कब्जा करने की अनुमति देना पूरी तरह से अवैध है।

हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया गया है कि आराजीयात जैर बहस मौजा दोतडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 264/2 रकबा 1.05 बीघा वर्तमान में अप्रार्थीगण के दर्ज रिकार्ड है की किस्म भूमि नाली दर्ज रेकार्ड रही है, ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान के विचारण योग्य प्रतीत होता है एवं प्रार्थी तहसीलदार, भदेसर द्वारा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 10(03)राज-6/01/पार्ट/17 दिनांक 23.09.2011 के क्रम में प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल



राजस्थान, अजमेर के विचारण योग्य प्रकरण होने से मौजा दोतडी, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी नम्बर 264/2 रकबा 1.05 बीघा के आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत अनुशंषा की जाकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है तथा मौजा दोतडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी नम्बर 264/2 रकबा 1.05 बीघा जो कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण के नाम पर दर्ज अभिलिखित है कि खातेदारी समाप्त किये जाने बाबत् रेफरेंस माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मय अनुशंषा के प्रेषित है। पत्रावली का मुसब्बा कायम किया जाकर हस्तगत मूल पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाई जावे। इसके साथ ही तहसीलदार, भदेसर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में राज्य पक्ष की प्रभावी पैरवी हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत् प्रेषित की जावे। इस न्यायालय से पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे तदनुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे।

“निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।”

(राकेश कुमार)

